<u>D;k jk"Vh; lj{kk d ennn LFkkuh; tuer lxg l ly>k, tku pkfg,</u>

!"#k tVyh

आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया है कि कश्मीर घाटी में सेना की उपस्थिति के मुद्दे पर फैसला घाटी में लोगों की राय जानकर लिया जाए। इसी नेता ने दो वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया था जिसमें जनता को यह फैसला करने की आजादी हो कि वह भारत में रहना चाहती है अथवा कोई अन्य फैसला लेना चाहती है।

देशी रियासतों के एकीकरण का काम सरदार पटेल ने किया था। लेकिन उसमें एक अपवाद था। वास्तव में जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों के बारे में पंडित जवाहर लाल नेहरु ने फैसले किए थे। जम्मू कश्मीर के बारे में उनके कुप्रबंध का नतीजा आज भी हमें झेलना पड़ रहा हैं। जम्मू कश्मीर को पृथक दर्जा देने के अलावा, वहां के 'लोगों की इच्छाओं पर गौर करने' का विचार नेहरु का सुझाव था। यह फार्मूला अन्य देशी रियासतों पर लागू नहीं था, जो भारत का हिस्सा बनीं। जनमत संग्रह का मुद्दा, जिसका पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, बड़ी कठिनाई से पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से कब्जा किए गए क्षेत्र से जोड़ा गया। आज जनमत संग्रह का मुद्दा न तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा है, न संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया का और न ही भारत–पाक द्विपक्षीय बातचीत का।

भारत की रक्षा पूरी तरह से केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। यह न तो राज्य का विषय है और न ही इसे स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सकता है। भारत की प्रभुसत्ता को बनाए रखना केन्द्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। भारतीय राज्य की मुख्य चिंता अपनी प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा करना है। विभाजन के समय से ही कश्मीर पाकिस्तान के अधूरे एजेंडा में है। पाकिस्तान को यह बात कभी हजम नहीं हुई कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की उसकी कोशिश विफल हो गई। पिछले 25 वर्षों के दौरान दो परम्परागत युद्धों में पराजित होने के बाद उसने सीमा पार से आतंकवाद के जरिये छद्म युद्ध छेड़ा है। गुमराह युवकों के कुछ स्थानीय आतंकवादी मॉड्यूल भी इसमें शामिल हो गए हैं।

भाजपा श्री अटल बिहारी वाजपेयी की इस घोषणा के प्रति वचनबद्ध है कि सभी मुद्दों का समाधान 'इंसानियत' से निकाला जाएगा। इसी धारणा से आतंकवाद का सफाया होगा, आतंकवादियों के ढांचे गिराए जा सकेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को सुख–सुविधा, शांति और अच्छा जीवन दिया जा सकेगा। घाटी से सेना को हटाने का काम इस उद्देश्य को हासिल करने के बाद ही किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र और वहां की जनता की रक्षा करने के लिए सेना की उपस्थिति तब तक आवश्यक है।

घाटी से सेना को हटाने का सुझाव पाकिस्तान का है। कुछ पृथकतावादी गुट उसकी इस मांग पर सुर में सुर मिला रहे हैं। यह खेद की बात है कि आम आदमी जैसी पार्टी जिसने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया, वह ऐसा रवैया अपनाए जो भारत के हितों के प्रतिकूल हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी फैसला लोकप्रियता अथवा जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। इनके बारे में कोई भी फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। जब तक आतंक का ढांचा मौजूद है, जम्मू कश्मीर में सेना की उपस्थिति आवश्यक है।

इससे मेरे दिमाग में एक ही बात आती है– कुछ विशेष परिस्थितियों में राजनैतिक दल जो बरसाती मेंढक की तरह उभरते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। उनके बढ़ने के साथ–साथ उनकी विचारधारा बनती है। इससे अटकलें लगती हैं और गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की वैचारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनावों के बाद ही उसके नेताओं से आरंभिक संकेत मिल रहे हैं कि हवाई अड्डों और प्राकृतिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, भारत की सुरक्षा पर उनका रवैया नरम और कमजोर है। वह अधिक सब्सिडी का समर्थन करती है जिसके लिए अधिक कर लगाना जरुरी होगा। पिछले दस दिन में शेख चिल्ली की तरह बयान दिए गए हैं और कोई ठोस सुझाव नहीं दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी में मौजूद समझदार लोग इस स्थिति को बदलेंगे। अन्यथा पार्टी का ग्राफ ऊपर की तरफ न बढ़कर तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा।